बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 18

भारी पड़ता लोकलुभावनवाद

एक ओर जहां केंद्र सरकार के आम बजट की प्रस्तुति के बाद उसका जमकर विश्लेषण होता है, वहीं राज्य सरकार के बजट को लेकर कम ही चर्चा होती है। ऐसा तब है जबकि राजस्व और व्यय को लेकर राज्य सरकार के निर्णय, केंद्र सरकार के घाटे और उसकी राजकोषीय गुंजाइश से कतई कम प्रभावकारी नहीं होते। हाल के दिनों में रुझान एकदम स्पष्ट रहे हैं। 2017-18 तक राज्य सरकारें मोटे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में अपने घाटे में एक फीसदी तक का इजाफा कर रही थीं जबकि केंद्र सरकार राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर इसमें आनुपातिक कमी कर रही थी। बहरहाल वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों के बजट का विश्लेषण बताता है कि कई छोटे राज्यों ने रुपये के मौजूदा संदर्भ में अपने घाटे को कम करने का प्रयास किया है। बिहार इस दिशा में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। उसने अपने घाटे को 35,000 करोड़ रुपये से कम करके 11,200 करोड़ करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इसके अपवाद भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का घाटा 3,000 करोड़ रुपये बढ़कर 44,000 करोड़ रुपये पहुंच गया। तमिलनाडु ने अपना घाटा 3,300 करोड़ रुपये बढ़ाकर 44,500 करोड़ रुपये पहुंचा लिया जबकि पश्चिम बंगाल का घाटा 6,000 करोड़ रुपये बढ़कर 29,700 करोड़ रुपये हो गया।

यह बात स्पष्ट है कि लोकलुभावन और चुनावी दबाव इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल का दावा है कि उसने करीब 10 लाख रोजगार तैयार किए हैं लेकिन उसने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 50,000 बेरोजगार युवाओं को एक लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की। कई राज्यों ने किसानों को आय के हस्तांतरण की घोषणा की है। झारखंड और पश्चिम बंगाल ने एक एकड़ जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार 12 लाख किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपये डाल रही है और उसने भूमिहीन श्रमिकों को 12,500 रुपये देने का वादा भी किया है। तेलंगाना ने किसानों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये देने का वादा किया है। अन्य स्थानों पर भी तरह-तरह की ग्रामीण सहायता प्रदान की जा रही है। आंध्र प्रदेश किसानों के कच्चे माल के लिए 5,000 करोड़ रुपये व्यय कर रहा है। उसने बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस शासन वाले कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी की जा रही है जबकि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। भाजपा शासित एक अन्य राज्य असम में वधुओं को 10 ग्राम सोना देने का वादा किया गया है। सर्वानंद सोनोवाल की सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले राज्य के प्रभावशाली तबके के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए खेल और कला जगत की हस्तियों को आकर्षक राशि देने की घोषणा की है।

वित्त आयोग ने राज्यों के घाटे की भरपाई के नियम सख्त किए हैं। यानी ऐसे व्यय की भरपाई करना अब बहुत जटिल हो गया है। हालांकि राज्य कड़ा परिश्रम कर रहे हैं कि राजस्व घाटे को शून्य और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 फीसदी के स्तर के आसपास रखा जाए लेकिन भरपाई के अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। यही कारण है कि जिन राज्यों के घाटे में कमी आ रही है उनकी बकाया देनदारी भी बढ़ रही है। ब्याज भुगतान हर वर्ष अधिक राजस्व खा रहा है। जबकि राज्यों को घाटे का लक्ष्य हासिल करने के लिए नकदी अधिशेष बनाए रखना होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह किसी भी दृष्टि से अच्छा संकेत नहीं है।

अजय मोहंती

मुश्किल दौर से गुजर रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था

पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी सहायता में कमी आ रही है। भारत के साथ हालिया तनातनी ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं **शुभमय भट्टाचार्य**

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को तुरंत विदेशी मदद की जरूरत है लेकिन भारत के साथ जारी टकराव ने उसकी कठिनाइयां बढ़ा दी हैं। विदेशी मदद के लिए उसके पास मुख्य तौर पर दो रास्ते हैं। पहला चीन और दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)। पाकिस्तान को 2017-18 में कुल जितना विदेशी कर्ज मिला था, उसका 40 फीसदी से अधिक हिस्सा चीन और आईएमएफ से आया था। पाकिस्तान विदेशों से लगभग इतना ही व्यावसायिक ऋण लेता है। इस तरह दोनों माध्यमों से मिलने वाला विदेशी कर्ज पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 30 फीसदी है।

प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद इमरान खान ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा चीन के साथ किए गए सौदों को फिर से खोलने का फैसला किया था। शरीफ ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपैक) के तहत चीन के साथ 62 अरब डॉलर का सौदा किया था। इससे चीन असहज हो गया है क्योंकि इमरान की ज्यादा दिलचस्पी आईएमएफ के राहत पैकेज में है।

यह एक राहत पैकेज होगा क्योंकि रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पास केवल एक महीने के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार है। हालांकि पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय इन आंकड़ों से इत्तफाक नहीं रखता है। नवंबर में एसऐंडपी ने पाकिस्तान की दीर्घावधि सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग घटाकर बी से बी माइनस कर दी थी। एजेंसी का कहना था कि पाकिस्तान में आर्थिक विकास की भविष्य लचर है और साथ ही विदेशी और राजकोषीय दबाव भी बढ़ गया है। इस रेटिंग का मतलब है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चिंताजनक स्थिति में है।

पिछले सप्ताह पूरे पाकिस्तान में हवाई अड्डे एक दिन से अधिक समय तक बंद रहे। इसके कारण देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी हालत बद से बदतर हो गई। दूसरे आंकड़े और भी खराब स्थिति बयां करते हैं। पाकिस्तान सरकार ने 2017-18 में चालू कीमतों पर आधारित जीडीपी विकास दर के 7.61 फीसदी रहने का अनुमान जताया है लेकिन रेटिंग एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी रुपये में गिरावट के कारण अमेरिकी डॉलर में मापी गई जीडीपी 2019 और 2020 में वास्तव में और सिकुड़ सकती है।

आंकड़ों में इस तरह के बदलाव आईएमएफ ने पाकिस्तान को सख्त सांख्यिकी प्रणाली में डाल दिया है। आईएमएफ द्वारा इस साल जनवरी में जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक पाकिस्तान ने आखिरकार नैशनल समरी डेटा पेज के जरिये वर्धित सामान्य डेटा प्रसार प्रणाली (ई-जीडीडीएस) की सिफारिशों को लागू कर दिया है।

आईएमएफ ने इससे पहले अंतिम बार जून 2017 में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का सालाना लेखाजोखा खंगाला था। यह एक असामान्य बात थी क्योंकि यह आईएमएफ चार्टर के तहत एक सालाना प्रक्रिया है। सच्चाई यह है कि अधिकांश देशों को तो यह सालाना अनुष्ठान भी गवारा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अलग मिट्टी का बना है। पिछले 30 साल से उसे करीब-करीब हर साल आईएमएफ और विश्व बैंक ने निगरानी की सालाना अनुमति के दायरे से परे जाकर पाकिस्तान की गहराई से पड़ताल की। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 12 राहत पैकेज दिए हैं जो एशिया में किसी भी देश को दिए गए सर्वाधिक पैकेज हैं। यही वजह है कि आईएमएफ को पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की गहराई से जांच करनी पड़ी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

लेकिन गहन जांच के बावजूद पाकिस्तान की 13वीं बार राहत पैकेज लेने की कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान इस साल जनवरी से इसके लिए आईएमएफ से बातचीत कर रहा है। उसकी नाकामी के दो कारण हैं। इसमें एक चिंता यह है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल चीन के ऋण के भुगतान में कर सकता है। देश के बजट दस्तावेजों के मुताबिक यह राशि 10.8 अरब डॉलर है। कार्यकारी बोर्ड के आकलन में कहा गया है, 'बाहरी दबावों, समायोजन मौद्रिक रुख और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ज्यादा आयात के कारण पिछले वित्त वर्ष के दौरान पाकिस्तान की राजकोषीय स्थिति डांवाडोल हुई।' दूसरे शब्दों में आईएमएफ ने इस बात की गारंटी मांगी है कि उसके और चीन के कर्ज को आपस में नहीं मिलाया जाएगा। पाकिस्तान ने 27 देशों से कर्ज ले रखा है।

दूसरा कारण यह है कि आईएमएफ पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वह अतिरिक्त राजस्व उपायों से राजकोषीय अनुशासन को मजबूत करे और खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करे। लेकिन वह सामाजिक योजनाओं के लिए खर्च जारी रख सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे रक्षा खर्च में कटौती करने को कहा गया है जो उसके सालाना बजट का 20 फीसदी से भी अधिक है। भारत में रक्षा खर्च बजट का 11 फीसदी है। पिछले सप्ताह भारत के साथ तनातनी के बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने बजट में से एक निश्चित राशि निकाली है।

आईएमएफ ने साथ ही पाकिस्तान स्टेट बैंक को मुद्रास्फीति के जोखिमों और व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए उपाय करने को कहा है लेकिन ऐसा करना मुश्किल है। विदेशी मुद्रा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता पैदा करती है जिससे कीमतें ऊंची बनी रहती हैं। चूंकि पाकिस्तान को 50 फीसदी बाहरी कर्ज बाजारों से जुटाना है, इसलिए उसे कर्जदाताओं को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा ताकि उनकी पाकिस्तान में दिलचस्पी बनी रहे।

पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा की भारी कमी है और यही वजह है कि उसने इसे बढ़ाने के लिए नए-नए उपाय करने शुरू कर दिए हैं। वह उन गिने चुने देशों में से एक है जहां मजदूरों को बाहर भेजने के लिए एक अलग मंत्रालय है। सरकार मजदूरों को खाड़ी सहित विभिन्न देशों में रोजगार के अवसरों को तलाशने में मदद करती है। इसके लिए अलग से बने मंत्रालय के पास 600,000 से अधिक लोगों के आंकड़े हैं। पाकिस्तान की एक और नीति तंबाकू को बढ़ावा देने की है। उसके वित्त मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उसने तंबाकू के बीजों के निर्यात और विश्लेषण के लिए फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि विश्लेषण रिपोर्ट से भविष्य में देश में अच्छी गुणवत्ता के तंबाकू के उत्पादन में मदद मिलेगी और इसका निर्यात किया जा सकेगा।

बजट में विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों के लिए एक लॉटरी का प्रस्ताव है। इसके तहत अगर वे वैध माध्यमों से स्वदेश पैसा भेजते हैं तो मासिक लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हैं।

कृषि क्षेत्र के समग्र सुधार के लिए कर्ज माफी नाकाफी

खेती-बाड़ी

सुरिंदर सूद

कृषि उत्पादों के विदेशी कारोबार पर लगने वाले शुल्क का ढांचा ऐसा हो कि निर्यात को प्रोत्साहन मिले और केवल आवश्यक वस्तुओं का ही आयात किया जाए। आयातित उत्पादों की भारत आने के बाद लागत घरेलू उत्पादों के लिए तय एमएसपी से न्यूनतम 10 फीसदी अधिक हो।

किसानों को कर्ज माफी या आय समर्थन जैसी चैरिटी की जरूरत नहीं है। किसानों के राष्ट्रीय संगठन भारतीय कृषक संघ कंसोर्टियम (सीफा) का कहना है कि 'किसानों को सम्मान के साथ जीने के लिए अपनी उपज पर वाजिब प्रतिफल से होने वाली कमाई की जरूरत है।' यह संगठन अन्य कृषि समूहों की तुलना में अलग राय रखता है। अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े कृषक संगठनों की तरह यह समूह किसानों का कर्ज माफ करने और दूसरे वित्तीय अनुदानों की मांग नहीं कर रहा है। सीफा की मांगें गैर-राजनीतिक होने के साथ ही कृषि को अपने आप में सक्षम बनाने वाली नीतियां बनाने से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा सीफा दूसरे कृषि संगठनों की तरह जीन-संवर्द्धित (जीएम) फसलों का विरोध करने के बजाय कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल का पक्षधर है। वह कृषि कार्य को लाभदायक बनाने के लिए नैनो, अंतरिक्ष, नाभिकीय, सूचना एवं जैव-प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के पक्ष में है। इस तरह सीफा का अभियान मूलत: तकनीक एवं ज्ञान पर आधारित कृषि विकास को लेकर है जिसमें कारगर मार्केटिंग हो और किसानों को केंद्र में रखते हुए नीतियां बनाई जाएं।

इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सीफा ने विस्तृत राष्ट्रीय कृषि एजेंडा तैयार किया है और अगले 10 वर्षों तक सरकार से इस पर चलने का अनुरोध करता है। इसका व्यापक उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सालाना 4 फीसदी की वृद्धि दर हासिल करना है जो फिलहाल 2-3 फीसदी ही है। ऐसा होने पर कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के बीच वृद्धि दर का फासला कम हो सकेगा। इसके लिए कृषि को आर्थिक विकास के केंद्र में रखने की जरूरत है। कुछ उसी तरह जिस तरह आर्थिक सुधारों की शुरुआत से ही उद्योग, व्यापार, सेवाएं एवं दूसरे क्षेत्रों को अहमियत दी जाती रही है। सीफा कृषि मंत्री को उप प्रधानमंत्री का दर्जा देने के साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट लाने की भी बात करता है। इस एजेंडे में कृषि की जिम्मेदारी उन अधिकारियों को सौंपने की बात कही गई है जो खेती के बारे में थोड़ी-बहुत समझ रखते हों।

सीफा के इस एजेंडे में उन बिंदुओं पर भी ध्यान दिया गया है जिन्हें अभी तक वाजिब तवज्जो नहीं मिलती थी। इनमें जमीन एवं पट्टे पर खेती करने से संबंधित नियम, कृषि मार्केटिंग को नई धार देने, खेती कार्यों में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने और ढांचागत क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने, कृषि प्रसंस्करण और कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार पाने वाले श्रमिकों को किसानों के खेतों में भी काम करने की मंजूरी दी जानी चाहिए। यह लागत साझा कर कृषि श्रम की बढ़ती किल्लत दूर की जा सकेगी।

इसके अलावा सीफा किसानों के आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए दीर्घावधि नजरिये से टिकाऊ कृषि नीतियों का पक्षधर है। मुद्रास्फीति नियंत्रण पर केंद्रित नीतियों के चलते विपरीत हालात में औचक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। आयात-निर्यात शुल्क में बार-बार होने वाले बदलाव और कृषि उत्पादों के विदेशी एवं घरेलू कारोबार पर लगने वाली तमाम बंदिशें कृषि उत्पादकों की कीमत पर उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने पर केंद्रित होती हैं। कृषि उत्पादों के विदेशी कारोबार पर लगने वाले शुल्क का ढांचा ऐसा हो कि निर्यात को प्रोत्साहन मिले और केवल आवश्यक वस्तुओं का ही आयात किया जाए। आयातित उत्पादों की भारत आने के बाद लागत घरेलू उत्पादों के लिए तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम-से-कम 10 फीसदी अधिक हो ताकि स्थानीय उपज पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी संशोधित करने की जरूरत है ताकि व्यापक उपभोग वाले कृषि उत्पादों के व्यापार पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकें।

सीफा का एक और उल्लेखनीय प्रस्ताव यह है कि कृषि एवं सिंचाई को संविधान की राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया जाए जिससे केंद्र सरकार को इन क्षेत्रों के विकास में अधिक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिले। वैसे इस प्रस्ताव पर अमल कर पाना काफी मुश्किल है। कृषि क्षेत्र को ऋण आवंटन, फसल बीमा, आपदा राहत, विदेश व्यापार और तकनीक प्रोत्साहन जैसे कई अहम मुद्दों को केंद्र सरकार ही काफी हद तक देख रही है। राज्य सरकारें तो बीज, बिजली, सहकारी समितियों और कृषि संबद्ध सेवाओं की ही देखभाल करती हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश क्षेत्रों की हालत खस्ता है। राज्यों की खराब आर्थिक सेहत के चलते सिंचाई क्षेत्र में फंड का अभाव रहता है। ऐसे में अगर सिंचाई को समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है तो केंद्र की सीधी निगरानी में रहने से उसे भी काफी लाभ होगा।

आम चुनावों को करीब आते देख सीफा विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। खासकर क्षेत्रीय दलों से उसे अधिक उम्मीदें हैं। भविष्य में क्षेत्रीय दलों की भूमिका काफी अहम होने की संभावना के चलते सीफा उनसे अपने चुनावी घोषणापत्र में इन बिंदुओं को जगह देने का अनुरोध कर रहा है। ये दल अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें इससे फायदा ही होगा क्योंकि सीफा के अधिकांश सुझाव न केवल सोचे-समझे हुए हैं बल्कि वे नतीजों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

कानाफूसी

राज्यसभा का लालच!

तमिलनाडु के दो प्रमुख द्रविड़ राजनीतिक दल जुलाई में खाली होने जा रही राज्यसभा सीटों का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के पहले गठबंधन के औजार के रूप में कर रहे हैं। जून में छह राज्यसभा सदस्यों की सीट खाली होने जा रही है और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम और द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम दोनों ने अपने छोटे साझेदारों पट्टालि मक्कल काची और मरुमलारची द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम को एक-एक सीट की पेशकश की है। चूंकि तमिलनाडु विधानसभा में 21 सीट खाली हैं इसलिए इन वादों का पूरा होना काफी हद तक इन सीटों के उपचुनाव नतीजों पर निर्भर करेगा। इस बीच अभिनेता से राजनेता बने विजयकांत की देशीय मुरपोक्कु द्रविड़ कषगम ने शायद इन दोनों में से किसी दल के साथ गठजोड़ में देरी इसलिए की क्योंकि उसे राज्यसभा सीट की पेशकश नहीं की गई थी।

व्यवहार बरकरार

राफेल सौदे को लेकर समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार और याचियों के बीच गरमागरम बहस के बावजूद दोनों दलों के बीच पेशेवर व्यवहार में कोई कमी नहीं आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी भी इस मामले में एक याची हैं। उन्हें दोपहर के भोजन के पश्चात प्रधान न्यायाधीश के कक्ष में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के साथ हाथ मिलाते देखा गया। उसके बाद के सत्र में सरकार ने याचियों पर सरकारी गोपनीयता कानून के अधीन कार्रवाई करने की धमकी दी और कहा कि जिन दस्तावेजों पर वह याचिका दाखिल की गई है, वे रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं।

आपका पक्ष

दिल्ली में आप और कांग्रेस की राह जुदा

कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाई ने दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर आप के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया है। दरअसल कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन करने का आग्रह किया था। दिल्ली की प्रदेश इकाई आप पार्टी से किसी तरह के गठबंधन का विरोध कर रही थी जिसे देखते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने आप से गठजोड़ नहीं करने का निर्णय किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने कहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और राज्य में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की सभी सात लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस और आप के बीच मतों के विभाजन से इस बार भी भाजपा को फायदा मिल सकता है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक बयानबाजी आम जनता की समझ से बाहर होती जा रही है। राजनीति में कदम रखते हुए वे बार-बार कांग्रेस और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद भी कांग्रेस लगातार उनके निशाने पर रही और अब लोकसभा चुनाव के

कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है

सामने आते ही वह कांग्रेस से गठबंधन की बात करने लगे। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस द्वारा गठबंधन से इनकार करने पर वे फिर पुरानी बोली बोलने लगे और कहा कि कांग्रेस भाजपा विरोधी मतों को विभाजित कर भाजपा की मदद कर रही है। हालांकि स्पष्ट हो गया कि भाजपा, कांग्रेस और आप अपने-अपने उम्मीदवारों के साथ लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगी। आम जनता चुनावों में इन दलों का राजनीतिक भविष्य तय करेगी लेकिन पार्टियों को इस बात ध्यान रखना चाहिए कि उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है और कहीं चुनाव जीतने के लिए वे अपनी ही विचारधारा से अलग राह पर तो नहीं जा रहे।

नफीसा, नई दिल्ली

ई-कॉमर्स में जियो की दस्तक

खबर है कि दीपावली के मौके पर रिलायंस जियो ई-कॉमर्स क्षेत्र में धमाकेदार दस्तक की तैयारी कर रही है। अभी तक फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे और एमेजॉन इंडिया अपने ग्रेट इंडियन दीवाली सेल के जरिये एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती रही हैं। ऐसे में जियो के इस क्षेत्र में आने से प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाएगी। आरआईएल ई-कॉमर्स कारोबार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है और कंपनी अक्टूबर-नवंबर में देश भर में ई-कॉमर्स सेवा शुरू कर सकती है। कंपनी इसके लिए मुंबई, कोलकाता, और बेंगलूरु सहित छह शहरों में परीक्षण भी कर रही है। रिलायंस असंगठित क्षेत्र के स्टोर

_Zone_officia

आरआईएल टेलीकॉम, मीडिया और कॉमर्स क्षेत्र को आपस में मिलाने की तैयारी कर रही है। इससे मौजूदा कंपनियों में एक तरह की खलबली मच गई है। आने वाले समय में जियो के विस्तार पर कंपनियों और कारोबारियों, सभी की निगाहें होंगी।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।